



















## अवैध विदेशियों के मामलों में भारत को अमेरिका से सीख लेनी चाहिए

भारत, एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा भूभाग स्मार्ट फैसिंग रहित है, जिसमें खुले समुद्री क्षेत्र हैं तथा कुछ स्थानों पर नदी के खुले किनारे हैं। ये वो स्थान हैं जो अवैध रूप से भारत में घुसने वाले विदेशियों को अवसर प्रदान करते हैं। भारत की संस्कृति ही कुछ ऐसी है कि काम में रुचि रखने वाले गरीबों के लिए अर्थ उपार्जन के अवसर अन्य देशों की तुलना में यहां सहज रूप से मिल ही जाते हैं। क्योंकि भारतीय न सिर्फ सहिष्णु होते हैं अपितु उनमें गरीबों के प्रति सहायता, दया एवं करुणा कूट-कूट कर भरी हुई रहती है। भारत में शयद इसीलिए जगह-जगह पर आरामगाह/रात्रि विश्राम कक्ष, अन्नपूर्णा क्षेत्र, आश्रम खुले हुए हैं जहां बहुत कम टोकन राशि पर या निशुल्क भोजन और आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वो भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के भेदभाव बिना। दान-पुण्य में विश्वास रखने वाले भारतीयों का एक वर्ग इन स्थानों के लिए खुले मन से सेवा और आर्थिक मदद करता है। किन्तु इसे भारत का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सरकारों के चाहने के बाबजूद भी भारत से भृश्चार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भृश्चारी कोई न कोई रास्ता भृश्चार के लिए इजात कर ही लेते हैं। इसी बुराई के कारण घुसपैठियों का अवैध रूप से न सिर्फ भारत में घुसना आसान हो जाता है अपितु भारत में रहने के लिए आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, बोरर आई कार्ड, राशन कार्ड आदि) बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता है। कई विदेशियों को समय-समय पर इन नकली दस्तावेजों के साथ पकड़ा भी गया है। भारतीयों का इस तरह का व्यवहार ही दुनिया भर के घुसपैठियों को भारत में अवैध रूप से घुसने के लिए आकर्षित करता है। भारत में अवैध रूप से कितने विदेशी लोग रहे हैं, इसका सही-सही आंकड़ा कोई नहीं जानता। किन्तु अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी संख्या लाखों में है। इन अवैध रूप से रहे विदेशियों में एक वर्ग ऐसा भी है जो भारत में मौका मिलते ही आतंक वादी गतिविधियों को अंजाम देता है या नारकोटिक्स ड्रग तथा हथियार आदि की तस्करी जैसे गैर कानूनी धंधे में संलग्न रहता है, नकली करेसी प्रिंट कर चलन में लाता है तथा खुफिया रूप से भारत की सैन्य गतिविधियों की जानकारी भारत के दुश्मनों तक पहुंचाता है। ऐसी भी शंका व्यक्त की जा रही है कि इन्होंने मतदाता तथा आधारकार्ड जैसे हफ्तान पत्र गतल तरीके से प्राप्त कर लिये हैं जिसकी मदद से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बोरर कार्ड की शक्ति इन्हें राजनीतिक पार्टियों की शरण प्राप्त करने में मदद करती है। हाल ही में सिने स्टार सैफ अली खान के साथ घटी चाकू बाजी की घटना के बाद अब तो अपराधिक गतिविधियों में भी इनका हाथ प्रमाणिक रूप से सामने आने लगा है। इस तथ्य से भी शयद ही कोई इंकार करे कि अवैध रूप से विदेशियों का भारत में रहना सिर्फ देश की सुख्ता के लिहाज से खतरा मात्र नहीं है, अपितु आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। क्योंकि ये अवैध रूप से रहे विदेशी नागरिक न सिर्फ भारत के

नागरिकों का हक मारते हैं, अपनु देश के संसाधनों पर अनावश्यक दबाव डालते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर, और सभिंडी वाती सुविधाएं आदि। भारत में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों में मुख्य रूप से बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और कुछ अफ्रीकी आदि देशों के लोग का शामिल होना सामने आया है। ऐसा देखा गया है कि इनमें से कई लोग वैध वीजा पर भारत आते हैं, लेकिन वीजा की अवधि समाप्त होने पर अपने देश वापिस जाने की वजह भारत में ही रुक जाते हैं। वहीं कुछ लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के खुली सीमाओं के निरंतर अवैध रूप से घुसपैठ कर भारत में प्रवेश करते हैं तथा विभिन्न असंवैधानिक विविधियों को अंजाम देते हैं। भारत में घुसपैठियों की समस्या पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, मुंबई, और करल जैसे बड़े महानगरों में ज्यादा अंभीर है, किन्तु ऐसा नहीं है कि इन्होंने अन्य राज्यों में अपना ठिकाना न बनाया हो। हर राज्यों में ये अपने मददगार बोज ही लेते हैं। एनआरसी के तहत अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कुछ राज्यों में अरंभ भी हुई है, किन्तु कुछ राजनीतिक कारणों के चलते पूरे देश में अवैध विदेशी खोजों अभियान 'प्राथमिकता' के आधार पर अरंभ नहीं हो सका है। मेरी दृष्टि में यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इनकी उपस्थिति भारत की अंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से जायज नहीं ठहराई जा सकती। हम सब इस घटना से वाकिफ ही है कि भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिकी राष्ट्रपति से अच्छे सबध हैं, दाना देशों के मध्य भी संबंध अच्छे ही है फिर भी अमेरिका ने अपने देश और देशवासियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए भारत के नागरिक जो अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रह रहे थे एक अपराधी की तरह वापिस कर दिया। निश्चित रूप से इन भारतीयों ने गैरकानूनी रास्ता अपना कर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। अतः भारत को भी अमेरिका की तरह अपने देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को चुन-चुनकर बाहर निकालने की कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। तथा राष्ट्र हित में पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों को सरकार के इस अभियान में सहयोग देना चाहिए। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब विपक्षी पार्टियां सरकार पर विदेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए दबाव डालें। घुसपैठ रोकने के लिए यदि भारत को लगता है उसके कानून पर्याप्त नहीं हैं तो उसमें आवश्यक सुधार किये जाना चाहिए, साथ ही यदि सीमाओं को और अभेद्य बनाये जाने की जरूरत है, तो अविलंब इस पर काम शुरू होना चाहिए। घुसपैठ रोकने के लिए सार्वजनिक जागरूकता जैसे कदम उठाने की भी आवश्यकता है, ताकि कोई भारतीय विदेशियों की सहायता न करें और न ही पनाह देने पर विचार करें। मेरा ऐसा मानना है कि भारत को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए संतुलित और प्रभावी नीति अपनानी होगी, ताकि मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बना रहे।

## डॉ मनमोहन प्रकाश

देश के 22 करोड़ मुसलमानों का पवित्र त्यौहार रमजान 'रविवार से शुरू हो रहा है। प्रयागराज में समास हुए महाकुम्भ के बाद का ये एक बड़ा त्यौहार है। अब सवाल ये है कि क्या उत्तर पदेश की सरकार सूबे की मस्जिदों में सरकारी हैलीकाटर से नमाजियों पर पुष्पवृष्टि करेगी? पढ़ने वाले कहेंगे कि -क्या मूर्खतापूर्ण सवाल किया है? मस्जिदों पर भी कोई फूल बरसाता है। वहां तो केवल पुलिस की लाठियां बरसाई जाती हैं। रमजान का महीना महाकुम्भ की तरह हालाँकि पाप धोने का मौका नहीं है लेकिन इस महीने में लोग पूरे एक महीने उपवास कर लोकल्याण के लिए दुआएं करते हैं। पवित्र कुरआन का पारायण करते हैं, तरावीह की नमाज पढ़ते हैं और अपनी औकात के हिसाब से जकात [दान] भी देते हैं। एतेकाफ़ करते हैं और माह के अंत में मिलजुलकर ईद मनाते हैं। यानि ये आत्मशोधन और लोकल्याण की उपासना का महीना है लेकिन दर्भाग्य ये है कि किसी

होतीं थीं, लेकिन अब सरकार रोजा इफ्तार को पाप और तुष्टिअकरण मानती है इसलिए इस रिवायत को समाप्त कर दिया गया है। मौजूदा सरकार में तो एक भी मुसलमान मंत्री भी नहीं है जो बेचारे रोजदारों को इफ्तार की दावत दे दे।

महाकुम्भ में जैसे सनातनियों के पाप धुल जाते हैं वैसे ही माहे रमजान में रोजदारों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रोजा इफ्तार के लिए पकवानों की जरूरत नहीं होती, ये शृङ्खला का मामला है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप रोजेदार को एक खजूर और और एक गिलास पानी देकर भी इफ्तारी करा सकते हैं। ये महीना मुस्तहिक लोगों की इमदाद करने का है। इस इमदाद को आप जकात कहें या फित्र कहें या सदका कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजा मुसलमानों को 'जब्ती नफ्स' यानि आत्म नियंत्रण करना सिखाता है। परहेजगरी सिखाता है यानि ये एक तरह की हठ साधना है।

रोजा हिन्दुओं के अनेक कठिन ब्रते जैसा ही है। हमारे इशाक मियाँ के अब्द बताया करते थे कि रोजे का मतलब यह नहीं है कि आप खाएं तो कुछ न, लेकिन खाने के बारे में सोचते रहें। रोजे के दौरान खाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए इस्लाम के अनुसार पांच बातें करने पर रोजा दूटा आमा माना जाता है। ये पांच बातें हैं बदनामी करना, लालच करना, पीठ पीछे बुराई करना, झूठ बोलना और झूटी कसम खाना। अब्द कि मुताबिक रोजे का मतलब बस उस अल्लाह के नाम पर भूखे-पायसे रहना ही नहीं है। इस दौरान आंख, कान और जीभ का भी रोजा रखा जाता है। इस बात का मतलब यह है कि न ही तो इस दौरान कुछ बुरा देखें, न बुरा सुनें और न ही बुरा बोलें। रोजे का मुख्य नियम यह है कि रोजा रखने वाला मुसलमान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के दौरान कुछ भी न खाए रोजा मन सा वाचा, कर्मणा आत्मनियंत्रण का अवसर है। काम कोध मोहू और लोभ

# संपादकीय

## रमजान- क्या मस्जिदों पर भी फूल बरसायेंगे योगी ?

દમજાન મુખાયક

# ડી મનમાહન પ્રકારી

चंडीगढ़ में विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन पर	अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत	भाजपा?	चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें हल्के में न लिया
--	-----------------------------------	--------	---

किंग स्थल तक दूसरी सड़क बनाने के लिए बुलडोजर चलाया गया था। शहर के द्वारा उत्तराधिकारी विभागों के कारण तोड़फोड़ से व्यथित निवासियों द्वारा सड़क पर विरोध प्रदर्शन के बाद उचित इस विश्व प्रसिद्ध उद्यान की दीवार का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया था। रॅक गार्डन ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ जल के प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते। यह न केवल चंडीगढ़ आने वाले पर्यटकों के लिए बल्कि शहर के निवासियों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है, जो सप्ताहांत में विपणित पदार्थों से बनी इसकी अद्भुत जलाकृति को देखने के लिए यहां आते हैं। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने रॅक गार्डन को एक हिस्से से सड़क को गुजारने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इसकी विपरिताओं को खारिज कर दिया, जिसने एक रूप से पारिस्थितिकी संबंधी चिंताओं के लिए इसके पार्किंग स्थल को प्राथमिकता दी। एक गार्डन की दीवार के एक हिस्से को गुराए जाने पर सार्वजनिक विरोध ने निवासियों को पहले से कहीं अधिक दबाव उत्तराधिकारी उद्यानों के एक मॉडल के रूप में चंडीगढ़ के चरित्र की रक्षा के लिए एक विदेशी शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। क्या राजनीति से उबर्गी हैं कंगना ?

कसी कारण के अनुपस्थित रहने पर भाजपा लोकों में चिंता व्याप्त है। वह हिमाचल प्रदेश मंडी स्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र से कई सालों से गायब हैं। वह बजट स्त्र के पहले नाथे भाग में संसद से भी अनुपस्थित रहीं, परिस्थिति रजिस्टर में उनका नाम शून्य दर्ज कर्या गया। ऐसा लगता है कि वह अपनी कल्प इमरजेंसी और मनाली में अपने नए बुले रेस्तरां माउंटेन स्टोरी के प्रचार में नायिक रुचि रखती हैं। जनवरी से, वह अपने सफरों के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुंबई और मनाली के बीच आना-नाना कर रही हैं।

दुर्भाग्य से, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नम्बर प्रदर्शन नहीं किया है। इसे प्रतिकूल अभिक्षा भी मिली है। उनके रेस्तरां की अफलता का आकलन करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मंडी में उनके लोग इस बात परेशान हैं कि वह मनाली तो अक्सर नाती रहती है, लेकिन पड़ोसी मंडी के लिए समय नहीं निकाल पातीं, जहां मतदाता नसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर हैं। बजट स्त्र के पहले भाग में संसद उनकी अनुपस्थिति पिछले दो सत्रों में नकी स्पष्ट उपरिस्थिति के बिल्कुल विपरीत है, जिसके दौरान उहोंने टीवी कैमरों के आगे राहुल गांधी पर निशाना साधने में अफी समय बिताया।

क्या शिंदे से पीछा छुड़ना चाहती है

जाएगा जो कि उन्हें लाभों का बढ़ावा दिलाया, यह वे ही थे जिन्होंने 2020 में उद्घव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करके और भाजपा के साथ एक वैकल्पिक सरकार बनाकर सरकार बदली थी।

**झारखण्ड में विपक्ष के नेता को लेकर भाजपा असमंजस में**

ईस सालों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता की नियुक्ति में देशी और विभिन्न संवैधानिक पदों को भरने वे फैसले को रोकने के लिए किसी राजनीतिक दल को फटकार लगाई है। इससे भाजपा के लिये परेशानी की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि उसने झारखण्ड विधानसभा में अपने नेता नियुक्त नहीं किया है, जबकि चुनावों में तीन महीने से अधिक समय पहले संपन्न हो चुके हैं।

झारखण्ड में पार्टी में निर्णय लेने वाले असमर्थता दिख रही है, क्योंकि भाजपा लगातार दूसरी बार हार के बारे में सोच रही है। आएसएस आदिवासी इलाकों में कड़ी मेहनत कर रहा है। ऐसा लगता है कि पार्टी विपक्ष के नेता के पद के लिए आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाने या अपने पारंपरिक वोट आधार उच्च जातियों और ओबीसी से किसी को आगे रखने के बीच फैसले नहीं कर पा रही है। इस बीच, झारखण्ड वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधीक्षी हो रहे हैं और भाजपा के अनिर्णय का फायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं।

जान यारा है कि लोगों में हालात की विभिन्नता है। अनुमान लगाएँ कि द्रव्यों का प्रतिक्रिया करती हैं। यानि चाँद सियासित नहीं करता। चाँद दोनों को क्या सभी को दर्शन देता है। चन्द्र सबका है। चाँद मियां का भी और चंद्रशेखर का भी। सनातनियों का भी और गैर सनातनियों का भी। आप कह सकते हैं कि काफिरों का भी होता है चाँद। वैसे रमजान इस्लाम कैलेंडर का नौवां महीना होता है। माना जाता है कि सन् 610 में लेयलत उल-कद्र के मौके पर मुहम्मद मद साहब को कुरान शरीफ के बारे में पता चला था। यूं रंजन का मतलब प्रखर होता है।

## राकेश अचल

ग्रीन या डिजिटल इडिया | सर्वोच्च नियमों की विवरण | [www.indianexpress.com](http://www.indianexpress.com)

अलग-अलग मापदण्ड  
मापन हैं दा भारत 1947

स्वतंत्रता के बाद से ही पर्यावरण योजनाओं के लागू होने के साथ-साथ विज्ञान टेक्नोलॉजी उद्योग और अर्थर्थक योजनाओं के विकास के साथ-साथ कृषि के विकास पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देता आया है। परिणामस्वरूप आज 76 वर्ष के बाद भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दौड़ में शामिल हो चुका है। अब भारत के सामने पर्यावरण बचाने, कृषि तथा



है इतना किसी भी अन्य देश को नहीं हो रहा है। इसी कार्यक्रम में प्राकृतिक बिचौलियों की उपस्थिति को भी रोका जा सकता है।



संसाधनों के वितरण प्रकार और गुणवत्ता को जलवायु परिवर्तन से बचाने का प्रयास भी शामिल है। भारत में इसी संदर्भ में ग्रीन इंडिया जैसी अवधारणा को आत्मसात किया है ग्रीन इंडिया तथा परिस्थितिकी सुधार को संरक्षण दिया है उसमें केंद्र व राज्य सरकारों ने मिलकर एक दशक के लिए लगभग 40, हजार करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान भी दर्शाया है। सरल शब्दों में ग्रीन इंडिया मिशन को जलवायु परिवर्तन की अनुकूलता को अंदर से देखा जाए उसमें कारबन में कटौती तथा परिस्थिति तंत्रों में मजबूती लाने का प्रयास किया जाएगा, इसके अंतर्गत बंजर वाली भूमि पर 50 लाख हेक्टेयर पर पेड़ लगाना और 50 लाख हेक्टेयर जमीन पर बढ़ते हुए वनों का संरक्षण भी शामिल है। जिसके फलस्वरूप 30 लाख परिवारों को रोजगार मुहैया कराना साथ ही 50 से 60 लाख तन तक कार्बन डाइऑक्साइड में कमी लाने का लक्ष्य तय किया गया। इस तरह ग्रीन इंडिया में भारी भरकम बजट खर्च करने की परियोजना तैयार की गई है। निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन में होने वाले नुकसान को इस योजना से रोका जा सकता है। वहीं दूसी ओर यदि डिजिटल इंडिया की बात करें तो ज्ञान के आधारित अर्थव्यवस्था में सुधार डिजिटल पद्धति से ही लाया जा सकता है। भारत देश जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटलीकरण अत्यंत आवश्यक भी दिखाई देता है। डिजिटल विकास के पास भारत देश में दीमक की तरह फैले हुए भ्रष्टाचार

# सरसद और सर्वाध्य न्यायालय

रा 20 जनवरी, 1950 का लातू स्वतन्त्र भारत के संविधान में पहला संशोधन किया था तो हिन्दू महासभा व उसके वैचारिक विधियों के द्वारा इसे सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में चुनौती दी गई। हालांकि चुनौती यूसीएल (पब्लिक यूनियन आप सिविल नबर्टीज) जैसी नागरिक अधिकारों के लिए डंड़े बाती संस्था के माध्यम से दी गई थी। न्यायालय ने संशोधन को पूरी तरह संविधान सम्पत पाया और याचिका को खारिज कर दिया। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 19 किया गया था जिसमें अधिव्यक्ति की वर्तन्त्रता व आरक्षण को लेकर प्रावधान किये थे। यह संशोधन क्यों किया गया था, इसकी विपरीता एक अलग कहानी है जिसे इस स्तम्भ सीमित शब्दों में समेटना संभव नहीं है। यह शोधन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा लाया गया था और उससे तत्कालीन कानून मन्त्री बाबा साहेब अम्बेडकर विपरीत तरह सहमत थे। नेहरू जी ने जो संशोधन किया था उसका मूल यह था कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल अधिव्यक्ति की स्वतन्त्रता विपरीते आड़ में हिस्सक विचारों का प्रचार-प्रसार हीं कर सकता है। भारत का पूरा संविधान ही नवतावाक दे ईर्द-गिर्द घूमता है। पं. नेहरू ने यह पेश किये गये इस संशोधन पर उस समय विपरीते अन्तर्रिम संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर तौर पर कानून मन्त्री दो घटे तक बोले थे और होने स्वीकार किया था कि अधिव्यक्ति की वर्तन्त्रता को अविवल स्वरूप देने के जोश में ह इस पक्ष की अनदेखी कर गये थे। व्योक्ति वैचारिक हिस्सा का खुला प्रचार-प्रसार भारत

पचमल जनता पाटी का सरकार था। माररजा द्वारा इन्दिरा के नेतृत्व में जब बनी तो उसने इन्दिरा गांधी सरकार द्वारा किये गये कई संशोधनों को निरस्त कर दिया मगर प्रस्तावना के मामले में उसने कोई छेड़खानी नहीं की। जाहिर है कि कांग्रेस विरोधी जनता पाटी भी कहीं न कहीं संसद की सर्वोच्चता के समर्थन में ही थी। उसने इन्दिरा सरकार द्वारा 1971 में सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किये जाने के बुरुद्ध इसे संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा जनरूर बनाया मगर इसे मौलिक या मूलभूत अधिकारों की श्रेणी से बाहर ही रखा। इन्दिरा गांधी ने इस अधिकार को बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद मूलत्वी किया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी सर्वोच्च न्यायालय में बुनौती दी गई थी और न्यायालय ने इसे सम्पत्ति के मूल अधिकार के तहत ही अवैधानिक घोषित किया था। इसके बाद 1971 में चुनाव जीत कर श्रीमती गांधी ने संविधान में संशोधन करके बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। ऐसा करके इन्दिरा गांधी ने संसद की सर्वोच्चता ही आपित की। उस समय यह भी सरकारी संशोधन किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को हेन्डी में उच्चतम न्यायालय कहा जाये। तब वह साफ हुआ कि संसद कोई नया कानून बना कर अपनी सर्वोच्चता को स्थिर रख सकती है। मगर 1973 में केशवानन्द भारती केस ने इसकी सीमाएं नियत कर दीं। मौजूदा दौर में वह सवाल फिर से एक बार उभरा है। यह मामला अदालत द्वारा दोषी पाये गये राजनीतिक जीतों द्वारा पुनः चुनाव लड़ने का है। चुनावों के कानून जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951



